



2026:AHC:15394

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 40569 वर्ष 2025

हरदेवआवेदक
बनाम
उ० प्र० राज्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	मृत्युंजय सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना जगदीश पुरा, जिला आगरा में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 342 में विचारण की लम्बितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की याचना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुराशय से इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। गिरोह तालिका में उल्लिखित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गिरोह तालिका में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (b) में परिगणित गिरोह की गतिविधियों का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुष्प्रेरण या सहयोग नहीं किया है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या गवाहों से छेड़छाड़ करने की भी कोई सम्भावना नहीं है। दिनांक 05.10.2025 से कारागार में निरुद्ध आवेदक यह वचन देता है कि यदि स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों की अत्यधिक लम्बितता के दृष्टिगत विचारण के शीघ्र समापन की कोई सम्भावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** में पारित निर्णय का सहारा लिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों की लम्बितता स्वयं जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की जमानत याचना का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार की गई गिरोह तालिका में दर्शाये गये मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला भी नहीं बता सके।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंध को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, हम इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला मानते हैं। अतः वर्तमान जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

आवेदक हरदेव को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्य न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से विरत करने के उद्देश्य से उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद प्रारम्भ, (ii) आरोप-विरचन एवं (iii) बयान दर्ज करने के लिए नियत तारीखों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तब गवाही के लिए नियत तारीखों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में वह जमानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कोई भी वक्तव्य केवल इस जमानत आवेदन के विनिश्चय के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कहे गये किसी भी वक्तव्य से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतन्त्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।

21 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।